निवेश नियमों को सरल बनाना जरूरी

कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक

लखनऊ। प्रदेश में बेहतर कारोबारी माहौल के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों जमीन, भवन निर्माण, श्रम, उपयोगिताएं और अनुमति पर फोकस किया। सोमवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा गठित टास्क फोर्स ने नियामक ढांचे को बेहतर करने और राज्य में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

नियमों को सरल बनाने की जरूरत बताई। बैठक में बताया गया कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी में 5 फीसदी की मामूली वृद्धि भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दे सकती है। केंद्र सरकार के युवा मामलों की सचिव राजीवलोचन ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार के लिए नियमों में ढील देने पर जोर दिया। उन्होंने जमीन अभिलेख प्रमाणित करने, अनुमोदन समयसीमा कम करने और मिश्रित भूमि उपयोग को प्राथमिकता देने पर बात की।

उन्होंने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, उद्योग के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता और उद्योगों के लिए नियमों का गैर-अपराधीकरण करने का सुझाव भी दिया।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। ब्यूरो